

उत्तरांचल शासन
राज्य सम्पत्ति विभाग
संख्या: 154(1)/xxxii/2010
देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2010

अधिसूचना संख्या-154/xxxii/2010, दिनांक फरवरी, 2010 को प्रख्यापित " राज्य सम्पत्ति विभाग के आफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल, रेसकोर्स, देहरादून के कक्षों की आवंटन नियमावली (असांविधिक), 2010 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 7- सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 10- निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति विभाग
संख्या 154/xxxii/2009-5(3)/2009
दिनांक 17 फरवरी, 2010
अधिसूचना / प्रकीर्ण

राज्यपाल, विधान सभा सदस्यों को आवास आवंटन, किराये की वसूली, अनधिकृत अध्यासन वेदखली एवं कक्षों में दिये जाने वाली साज-सज्जा से संबंधित उत्तराखण्ड विधान सभा सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 2004 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

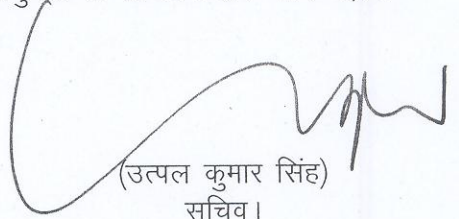
- 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा सदस्यों के निवास स्थान एवं अतिथि गृह सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, 2010" है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 के उपनियम (3) के पश्चात् उपनियम (4) का प्रतिस्थापन

- 2- "उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 2004" के नियम 4 में उपनियम (3) के बाद उपनियम (4) निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :-

आवास का
प्रदेशन और
उस पर
कब्जा

"(4) विधायक के निवर्तमान हो जाने अथवा पद छोड़ दिये जाने की तिथि से उन्हें आवंटित आवास एक माह के अन्तर्गत रिक्त करना होगा। विशेष कारणों से एक माह तक आवास रिक्त न किये जाने की दशा में विशेष परिस्थिति में यह अवधि राज्य सम्पत्ति अधिकारी की अनुमति से 15 दिन तक और बढ़ायी जा सकेगी।"


(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. _____ dated _____ for general information

Government of Uttarakhand
State Estate Department
No.154 /xxxii/2009-5(3)/2009
Dehradun: Dated...17...February, 2010
Notification
Miscellaneous

The Governor, with a view to further amend the Uttarakhand Accommodation for the Members of Legislative Assembly Rules, 2004 regarding allotment of accommodation to the Members of Legislative Assembly, recovery of rent unauthorised occupation, eviction and furnishings to be provided in the rooms, is pleased to accord sanction to make the following rules:-

Short title and
Commencement

1. (1) These rules may be called the Accommodation and Guest House for the Members of Uttarakhand Legislative Assembly (Amendment) Rules, 2010.

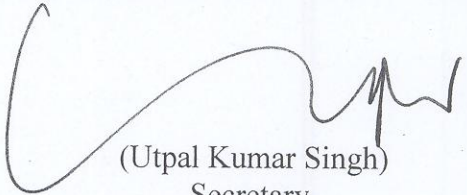
(2) They shall come into force at once.

Substitution of sub-rule (4) after sub-rule (3) of rule 4.

2. In the Uttarakhand Accommodation for the Members of Legislative Assembly Rules, 2004 after sub-rule (3) of rule 4, sub-rule (4) shall be added, as follows, namely:-

Allotment and
possession of
accommodation

(4) The Member of Legislative Assembly shall vacate the accommodation allotted to him or her within one month from the date of his or her retirement or vacating his post. In case the accommodation is not vacated upto one month due to special reasons, this period may be extended further upto 15 days in special circumstances with the permission of the State Estate Officer.


(Utpal Kumar Singh)
Secretary.